(10—19 years) and elderly population (65 years and above) as on 1st March, 1998 have been estimated to be 213.8 million and 42.2 million respesctively.

(b) One of the primary objectives of the Ninth Plan is to generate greater productive employment in the growth process itself by concentrating on sectors, sub-sectors and technologies which are more labour itensive in regions characterised by higher rates 6f unemployment and under employment.

(c) The schemes currently providing social and financial security to elderly people include old age pension provided by State Governments and under National Social Assistance Programme (NSAP), contributory and non-contributory provident funds. Health care to the elderly is provided through existing network of primary, secondary and tertiary health care institutions.. During Ninth Five-Year Plan the coverage under all these will be further improved.

उत्तर प्रदेश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम0पी0ए0डी0एस0) के लिए स्वीकृत धनराशि

1364. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद को "ससंद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख)31 मार्च, 1998 तक इनमें से प्रत्येक संसद-सदस्य द्वारा कितनी राशि खर्च की गई और कितनी राशि शेष हैं;

(ग)लोक सभा चुनाव हार चुके संसद-सदस्य तथा ऐसे संसद सदस्य जो राज्य सभा के सदस्य नहीं हैं उनके पास पड़ी बकाया राशि का किस प्रकासर उपयोग किया जाएगा; और

(घ) 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों (जो चुनाव हार चुके हैं अथवा सेवा निवृत हों गए हैं) के पास बकाया राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 1995-96 और 1996-97 के प्रत्येक वर्ष में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतयेक संसद सदस्य को 1 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई थी। उत्तर प्रदेश में 30.11.1998 तक वर्ष 1997-98 के लिए 50-50 लाख रूपए की पहली और दूसरी किश्तें क्रमश: 119 और 102 संसद सदस्यों के वास्ते अवमुक्त की जा चुकी हैं।

(ख)31.3.1998 तक उत्तर प्रदेश राज्य के संसद सदस्यों के संबंध में रिपोर्ट किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा "अनुपत्र" में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 185 अनुपत्र सं0 38)

(ग)और (घ) संसद सदस्य के बदल जाने के मामले में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की अधिशेष निधियों के उपयोग की प्रक्रिया संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 3.9 में निर्धारित की गई। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रतियां सभी संसद सदस्यों को परिचालित कर दी गई हैं।

Allotments from MPLADS for Private Organisations

1365. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many of the M.P. Local Area Development Scheme are being allotted to private colleges recognised by the UGC, private youth and women organisation etc. which are recognised by Government for the construction of Community Halls, buildings etc.; and

(b) the extent of such allotments made by M.Ps and accepted by the Local Government authorities in Srikakulam District of Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) As per the information received from the District collector, Srikakulam District of Andhra Pradesh, no such allocation has been made from MPLADS for private colleges. A total of 71 works relating to community all buildings, youth club buildings and Mahila Mandal buildings with an estimated cost of Rs. 52.50 lakhs were proposed by the MPs in that district from 1994-95 to 1997-98. Too that extent the sanctions were also accorded by the Collectors.

Release of Funds for MPLADS

1366. SHRI PRAKANTA WARISA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not released the full funds for 1998-99 to the Member of Rajya Sabha and Lok Sabha under the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS);

(b) if so, the reasons for not releasing the full amount of funds to them for the current year;

(c) by when the funds are likely to be released?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) As per the extent guidelines on MPLADS, release of funds under the scheme is made in two instalments keeping in view the physical and financial progress of works. Accordingly, from the year 1997-98 it was decided to release funds for the MPs in whose account the unsanctioned balance was less than Rs. 50 lakhs. As per this approved criteria, out of 790 MP's, 328 MPs (283 LS + 45 RS) and 165 MPs (143 LS + 22 RS) were found eligible for release of first & second instalment of funds respectively for 1998-99 on the basis of information received from the concerned District Collectors (DCs) as on 30.11.1998. Funds to remaining MPs could not be released as either unsanctioned balance was more than Rs. 50 lakhs or information was not received from the concerned DCs.

'(c) The remaining funds for 1998-99 would be released on receipt of reports from concerned DCs showing unsanctioned balance of less than Rs. 50 lakhs.

कच्छ में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन

1367. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया हैं;

(ख)यदि हां, तो इस जिले को किस आधार पर उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया हैं;

(ग)नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्छ में क्रियान्वित किए जाने वाले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ)आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं और चाले वित्त वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि का अद्यतन ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडपी) पाकिस्तान, बंगलादेश और म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों के सीमा ब्लॉकों में चालू हैं। अत: गुजरात के कच्छ जिले के बार्डर ब्लॉक, जिनकी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं।